(घ) पूरे देश में जमाखोरी-विरोधी अभियान को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है।

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा): (क) प्रधानमंत्री समय-समय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुशल कार्यान्वयन और यह सुनिश्चित करने पर कि आपूर्ति उपभोक्ताओं तक बहुत बल देते हैं।

(ख) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी में लगे और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों तथा उसके तहत जारी नियंत्रण आदेशों का अन्य प्रकार से उल्लंघन करने वाले बेईमान तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन और आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रवर्तन की राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर समीक्षा की जाती है। केंद्रीय सरकार को ऐसी सूचना नहीं मिली है कि राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में केंद्रीय सरकार की सलाह का अनुसरण नहीं कर रही है। राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई की सूचना केंद्रीय सरकार को आवधिक रूप से दे रही है।

केंद्रीय सरकार के पास आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन हेतु अलग से कोई तंत्र नहीं है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभागों के अधिकारी और कर्मचारी आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों और उसके तहत जारी नियंत्रण आदेशों को लागू करने के अपने कार्य के एक हिस्से के रूप में, निरीक्षण करते हैं और छापे मारते हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह सलाह दी गई है कि जब कभी भी यह महसूस किया जाए कि बेईमान तत्वों द्वारा सट्टेबाजी के लिए की गई जमाखोरी के कारण किसी आवश्यक वस्तु की उपलब्धता और मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तो वे जमाखोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाएं।

केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस संबंध में पत्रों और बैठकों के माध्यम से समय-समय पर सलाह देती है।

Cost of elimination of child labour

689. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to Government's estimates the cost of elimination of child labour comes to Rs. 12,720 per child;

(b) whether it is also a fact that International Labour Organisation has estimated the cost of elimination of child labour at Rs. 1,390/—; and

(c) if so, the reasons for the difference?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) and (b) No, Sir.

(c) Does not arise in view of reply to (a) and (b) above.

News-item regarding rising prices of pulses

690. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: SHRIMATI VEENA VERMA: SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleaesd to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report in the 'Statesman' of 23rd August, 1995 captioned, "price soar-buyers sore" regarding sky-packing prices of pulses, in the main commercial markets and in retail markets in the country; and

(b) if so, the comparative prices of each type of pulses and dals in January, April and September, 1995?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPTT. OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) (SHRI